□[डा० जगन्नाथ मिश्र]

में नई रेलवे लाइनों के निर्माण छोटी लाइनों से बड़ी लाइन में परिवर्तन, पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल, पटना के इर्द-गिर्द उपनगरीय रेल सेवा प्रारंभ किए जाने के संबंध में, पटना-हावड़ा, पटना-रांची, पटना मुजफ्फरपुर आदि आदि मार्ग पर नई रेल गाड़ियां चलाए जाने के संबंध में एवं राजकीय रेलवे पुलिस के विस्तार के संबंध में तथा राज्य में रेलवे के महाप्रबंधक का एक नया जोनल कार्यालय खोले जाने के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया। परन्तु औचित्य एवं जनहित के व्यापक तर्क इन सुझावों के साथ प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी अभी तक रेल मंत्रालय ने कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है। बिहार सरकार की ओर से आसनसोल खंड के विद्युतीकरण का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को दिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि बिहार में रेल सेवा का विस्तार केवल बिहार के हित मे ही आवश्यक नही है बल्कि राष्ट्रीय हित में इसकी उपयोगिता अधिक होगी। खनिज एवं जंगल पदार्थों के लिए, बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए रेल सेवा की उपयोगिता ली जा सकती है। बिहार का बहुत सा हिस्सा रेल सेवा से वंचित है जिससे इन भू-भागों में विकास की संभावना नहीं रहती है। इन पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन निर्माण के पीछे केवल वित्तीय हितों को नहीं देखा जाए बल्कि सामाजिक, आर्थिक लाभों को भी आंका जाए। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक हित में अगर पूंजीनिवेश पर दस प्रतिशत से भी कम आय हो तो भी यातायात में पूंजी लगाई जाए। रेल लाइन का विस्तारन यातायात एवं परिवहन व्यय को कम करने के उद्देश्य से भी किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए रेल सेवा मुख्य संरचना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में भी 17 करोड़ तथा 20 करोड़ का प्रावधान पुरानी लाइनों को नई बनाने में और छोटी लाइन को बड़ी बनाने तथा पुराने पुलों के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार राज्य में इन नए कार्यों के लिए पूजी का आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए बिहार की भावना है कि रेलवे के विकास में बिहार की उपेक्षा हो रही है। कोई भी नया कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है। 36 नई रेलवे लाइनें बनाने की अनुसंशा बिहार सरकार ने की जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण का मूल्य स्लीपर की लकड़ी देने का भी आश्वासन बिहार सरकार ने दिया है। अन्य राज्यों में रेल का विस्तार हो रहा है जहां की सरकार की ओर से ये प्रमुख व्यय भी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की ओर से व्यय वहन करने के बावजूद बिहार की योजना पर भारत सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की जो पुरानी लम्बित योजनाएं है उसमें शीघ्रता लाने की पूरी कोशिश करे।

Shifting of Union Carbide India Ltd. to Bombay

श्री नरेश सी. पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, स्पेशल मेंशन के

माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय को मैं इस सदन के माध्यम से लाना चाहूंगा। इस देश की जनता इस वाकया से वाकिफ है कि 3 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में जो गैस कांड हुआ था जिसमें 3 हजार के ऊपर लोग मारे गये थे और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने इस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को बंद कर दिया था उस कारखाने को महाराष्ट्र के अन्दर नये बम्बई शहर में वाशी में शिफ्ट किया जा रहा है। इस बात का विरोध करने के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि इस गैस की वजह से 3 हजार लोगों की हानि हो चुकी है और उसके बाद पिछली 31 अगस्त को उसमें जो बची हुई गैस थी वह दुबारा लीक होने की वजह से भगदड़ मच गयी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस कारखाने के लिए जो दूसरी जमीन जबलपुर के नजदीक मध्य प्रदेश ने मंजूर की थी, उस पर रोक लगा दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने राज्य में इस कारखाने को चालू नहीं होने देंगे। लेकिन यह कारखाना अब बम्बई के नये शहर वाशी में शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए फार्मल्टीज पूरी हो चुकी है। सिर्फ हमारे डायरेक्टर, एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र की अनुमति के लिए मामला रुका हुआ है। आज भी उस कारखाने में बड़ी मात्रा में गैस है और उसी कारखाने को यहां शिफ्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। वह एम.आई.सी. गैस जिससे तीन हजार लोग मारे गये थे यह गैस अभी उसमें बाकी है। और इसके साथ कम्पनी ने जो आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार को और केन्द्रीय सरकार को दिये हैं उनके अनुसार 20 टन एम.आई.सी. गैस जिसमें आपकी क्लोरोफार्म शामिल है। साथ साथ 19 टन क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, 49 टन क्लोरो बेनजीन है, 4 टन कार्बन टेटरा क्लोराइड है, 110 टन पेट्रोलियम कोक है, 2 टन मेथील क्लोराइड है। इस प्रकार के आंकड़े कम्पनी ने दिये है। लेकिन न तो उसे किसी ने गिना है और अगर कम्पनी के दिये हुए आंकड़ों पर हम भरोसा करते हैं तो यह बहुत बड़ी मात्रा गैस की है। अगर यह गैस कम्पनी महाराष्ट्र के बम्बई शहर वाशी में लगने जा रही है तो महाराष्ट्र की जनता के साथ आप खेल रहे हैं, उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद वहां लगता है तो बहुत गलत है। अगर केमिकल फैक्टरी को इस गैस की जरूरत है, यूनियन कार्बाइड को भारत में चलने देना चाहते हैं तो किसी केमिकल एक्सपर्टस के लोगों की टीम बनाकर उनके सुझाव लेकर रिमोट एरिया में इसको लगा सकते है। इससे यह होगा कि अगर मशीनरी में कोई गड़बड़ी होती है तो भोपाल जैसा कांड दुबारा न होगा यह कारखाना हिन्दुस्तान के किसी रिमोट एरिया में लगायें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा लेकिन बम्बई शहर वाशी में जहा पहले ही सैकड़ों इंडस्ट्रीज है वहा लगाना मुनासिब न होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी वहां से आते हैं आपको मालूम है कि वहां पर पूरी एक नयी हाउसिंग कालोनी बननी है। उस कालोनी में अगर महाराष्ट्र सरकार इसको परमिशन देती है तो यह

[श्री नरेश सी पुगलिया]

बहुत गलत होगा । मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि इसमें वह हस्तक्षेप करें और यह कारखाना महाराष्ट्र में या किसी भी स्टेट में लगाने का लाइसेंस तब तक न दें जब तक किसी केमिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती । उसके अनुकूल इस को किसी बड़े शहर में या जहां वह उचित समझे शिफ्ट किया जाये । साथ ही यह भी विनती करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस कम्पनी के बड़े अधिकारियों ने, लाइजन आफिसर ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालयों में बार-बार चक्कर लगाकर इस कारखाने को लगाने की परमिशन लेने की कोशिश की है मैं जानना चाहूंगा कि उस कारखाने को परमिशन देने के पीछे चाहे विरोधी पक्ष या सत्ता पक्ष के लोग हों जिन नेताओं का हाथ है उसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाये । मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे । इस कारखाने का नतीजा हमारे सामने है, तीन हजार से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं और हजारों लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं । आज भी मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों का इलाज करवा रही है। इसलिए इस मामले को सीरियसली लिया जाए और जिन्होंने महाराष्ट्र के अन्दर बम्बई शहर में इस कारखाने का ले जाने का षडयंत्र किया है, इसकी सी.बी.आई. के माध्यम से जांच की जाए । मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी इसमे हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र की जनता को राहत पहुंचायेंगे और इस कारखाने को बम्बई शहर में ले जाने से रोका जाना चाहिए ।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, the whole House associates with it. But Mr. V. M. Jadhav and Mrs. Sudha Vijay Joshi will speak on it.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय हमारे मित्र श्री नरेश पुगलिया जी ने जो मसला सदन में उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि भोपाल जैसी ट्रेजिडी बम्बई में भी इसके कारण हो सकती है। आप जानते हैं कि बम्बई हिन्दुस्तान की कमर्शियल केपिटल है, इंडस्ट्रियल सिटी है । वहां अगर ऐसी पोइजनस गैस फैलेगी तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के कारण मैं यह जानता हूं कि एक साइंटिस्ट ने साइनाइड को अपनी जबान पर टेस्ट किया जो उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, इतनी पोइजनस यह गैस होती है । बम्बई शहर में पहले से ही इतना पोल्यूशन है, वहां पर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धन्धे हैं, अगर वहां पर किसी कारण से यह गैस फैल गई तो, भोपाल में तो हजारों लोग मरे थे बम्बई में लाखों लोग मर जाएंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारखाने को महाराष्ट्र में लगाने से रोकें और अगर उसे लगाना ही है तो किसी रिमोट एरिया में लगाया जाए जहां लोगों की आबादी कम हो और आबादी कारखाने से दूर हो और उस कारखाने में सुरक्षा के पूरे प्रबन्ध किये

जाएं। किसी हालत में यह कारखाना बम्बई में नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं हमारे मित्र श्री पुगलिया जी ने जो मसला उठाया है उससे पूरी तरह से सहमत हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I think that both of you should also bring it to the notice of the Chief Minister of Maharashtra.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: हम जरूर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वे इस बारे में कदम उठाये।

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र) : :उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री पुगलिया जी ने जो प्रश्न उठाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके आपके लिए और हमारे लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी बम्बई से आते है और मैं भी बम्बई से आती हूं। आप जानते हैं कि बम्बई बहुत ही घनी आबादी का शहर है। ऐसे शहर में अगर इतना खतरनाक कारखाना बनेगा तो इससे बहुत ही बड़ी आपत्ति आ सकती है। इसलिए इतने बड़े शहर में यह कारखाना न हो क्योंकि पहले ही बम्बई के ऊपर बहुत सी आपदायें हैं। आप जानते है कि बम्बई महाराष्ट्र की और हमारे देश की शान है। इसलिए अगर इस शहर में यह कारखाना लगाया जाएगा तो बम्बई पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। मैं चाहूंगी कि इस कारखाने को बहुत ही रिमोट एरिया में लगाया जाए जहां पर आबादी न हो और जहां पर इस प्रकार की विपत्ति आने का डर न हो। बम्बई शहर में ऐसा कारखाना नहीं होना चाहिए और घनी आबादी के किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Many Members want to associate with this. I think the whole House wants to associate with this. We will take it like that.

Remunerative Prices for Sugarcane Growers

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा यह स्पेशल मेंशन अक्तूबर में शुरू होने वाले गन्ना सीजन के बारे में है और मेरे स्पेशल मेंशन की मंशा यह है कि आने वाले सीजन में गन्ने का जो मूल्य है वह कम से कम 32 रु. फी क्विंटल किया जाए। पिछले वर्ष सूखे के कारण हमारे किसानों की आर्थिक दशा खोखली हो गई। लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने इस सूखे का हिम्मत के साथ मुकाबला किया। हमारी सरकार ने भी हर मौके पर प्रधानमंत्री के निर्देश पर किसानों की सहायता की और जो भी सहायता संभव थी, वह मदद किसानों की है इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। सूखे के बावजूद किसानों ने गन्ने की भारी पैदावार की है और गन्ने के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है।देश के गन्ना बोने वाले किसानों को इस सदन को मुबारकबाद देनी चाहिये, बधाई देनी चाहिये। मान्यवर, अब अक्तूबर 88 से, एक महीने के बाद गन्ने